दिनांक : .०१.२०१९

प्रति,

माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार, १५२ बी, साउथ ब्लॉक,
रायसिना हिल, नई देहली – ११००११

विषय : केंद्र सरकार करोडों हिन्दुओं की श्रद्धास्थान श्रीरामजन्मभूमी (अयोध्या) पर राममंदिर निर्माण के लिए संसद में तत्काल कानून बनाए...

महोदय,

भगवान श्रीराम करोडों हिन्दुओं के श्रद्धास्थान हैं । उत्तरप्रदेश स्थित अयोध्यानगरी प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि है, यह सर्वदृष्टि से प्रमाण सहित सिद्ध हो चुका है । ३० सितंबर २०१० को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी उक्त स्थल रामजन्मभूमि है तथा यहां राममंदिर था, ऐसा निर्णय देकर उसे रामजन्मभूमि घोषित किया है । वर्तमान में यह अभियोग सर्वोच्च न्यायालय में न्यायप्रविष्ट है तथा प्रलंबित है; परंतु उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रमाणों के आधार पर अयोध्या की भूमि श्रीरामजन्मभूमी है, यह सिद्ध हो चुका है । श्रीराम मंदिर देश के करोडों हिन्दुओं की आस्था का विषय है । अतः हिन्दुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासन बिना किसी विलंब के संसद में कानून बनाए तथा राममंदिर के निर्माण का मार्ग खोल दे । इस पवित्र भूमि पर अभी तक हिन्दुओं को पूजा करने की अनुमति नहीं है । हिन्दूबहुल भारत में प्रभु श्रीरामजन्मभूमि पर हिन्दुओं को पूजा करने का अधिकार नकारा जाता है, इससे बडा हिन्दुओं का दुर्भाग्य और क्या होगा ! हिन्दुओं को इस स्थान पर पूजा करने की स्थायी अनुमति तत्काल दी जाए ।

*** इस संदर्भ में हम कुछ बातें निदर्शन में लाना चाहते हैं –**

१. ३० सितंबर २०१० को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'सुन्नी वक्फ बोर्ड' का दावा खारिज करते हुए कहा कि उस स्थान पर 'श्रीरामलला विराजमान हैं ।' यह भूमि श्रीरामजन्मभूमि है और मंदिर तोडकर विवादित वास्तु का निर्माण किया गया था, यह भी स्वीकार किया है ।

२. राममंदिर निर्मिति के लिए वर्ष १८५७ से आज तक अनेक हिन्दुओं ने बलिदान दिया है । इसमें वर्ष १९९२ में कार सेवकों के आंदोलन का विशेष उल्लेख करना पडेगा ।

३. 'अयोध्या में राममंदिर का निर्माण', यह घोषणा आजतक भाजपा के चुनावी घोषणाओं में केंद्रस्थान पर रही है । राममंदिर बने, यह करोडों हिन्दुओं की केवल मांग ही नहीं, अपितु वह हिन्दुओं की श्रद्धा का विषय है ।

४. कांग्रेस के कार्यकाल में श्री सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो सकता है, तो विकास और हिन्दुत्व के सूत्रों पर चुनकर आई भाजपा को राममंदिर का निर्माण करना निश्चित ही संभव है ।

५. तमिलनाडु में 'जल्लिकट्टू' नामक पारंपरिक खेल पर जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया था, तब वहां की तत्कालीन जयललिता सरकार ने दबाव बनाया तथा केंद्र ने उन्हें संबंधित कानून ही परिवर्तित करने हेतु कहा था । जिस कानून के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 'जल्लिकट्टू' पर प्रतिबंध लगाया था, उसमें ही परिवर्तन होने के कारण अपनेआप ही निर्णय परिवर्तित हो गया । भाजपा शासन ने एट्रोसिटी कानून के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश संसद में कानून बनाकर बदल दिया तथा तीन तलाक के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर कानून बनाया । यदि इतना सब हो सकता है, तो वर्ष २०१४ में जिस भाजपा शासन को हिन्दू जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश देकर सत्ताप्राप्ति करवाई, वह भाजपा शासन अध्यादेश जारी क्यों नहीं करता ?

६. आजतक भारतीय न्यायव्यवस्था का अनुभव देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकरण की सुनवाई प्रारंभ होने, शीघ्रता से प्रकरण पर निर्णय होने आदि में कितना समय बीतेगा, यह बताना अनिश्चित ही है । हिन्दू समाज भोली आशा लेकर भाजपा शासन से आस लगाकर बैठा है कि जो गत ७० वर्षों में जो नहीं हो पाया, वह अब भाजपा शासन के सत्ता में रहने पर होगा । यदि शासन मंदिर निर्माण के लिए कृति नहीं करता, तो समाज का केंद्र शासन और न्याय व्यवस्था से विश्वास उड जाएगा । हिन्दू और कितने समय न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे ? राज्य, केंद्र में बहुमत होते हुए सरकार को राममंदिर

के संबंध में इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए ।

७. गत कुछ दिनों से देशभर के विविध हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन और संत समाज एकत्रित आकर राममंदिर शीघ्रातिशीघ्र बनाने और उसके लिए अध्यादेश जारी करने की केंद्र सरकार से मांग कर रहा है तथा देश के विविध राज्यों में सार्वजनिक सभाएं ले रहा है, आंदोलन कर रहा है, निवेदन दे रहा है ।

इसलिए आनेवाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए हिन्दुओं की भावनाओं के धैर्य का बांध टूटने से पूर्व शासन राममंदिर का अध्यादेश जारी करने का निर्णय ले ।

*** इस संदर्भ में हमारी मांगें निम्नांकित हैं –**

१. संसद में हिन्दुओं द्वारा दिए गए बहुमत के आधार पर श्रीराममंदिर निर्माण के लिए कानून बनाकर उसके आधार पर अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण प्रारंभ करें ।

२. वर्तमान कें श्रीरामजन्मभूमि पर प्रभु श्रीराम की मूर्ति एक कपडे के तंबू में रखकर एक प्रकार से उसका अनादर ही किया जा रहा है । इस स्थान पर श्रद्धालु किसी प्रकार की पूजा नहीं कर पाते । यह रोकने के लिए भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण करने से पूर्व निकट ही एक अस्थायी छोटा मंदिर बनाया जाए, वहां प्रभु श्रीराम की मूर्ति की स्थापना की जाए तथा हिन्दुओं को विधिवत पूर्जा–अर्चना, धार्मिक विधि करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ।

३. जब तक उक्त मांगे पूर्ण नहीं होती, तब तक श्रीरामजन्मभूमि पर प्रभु श्रीराम की विधिवत पूजा करने हेतु हिन्दुओं को स्थायी रूप से विशेष अनुमति दी जाए ।

४. वर्तमान में इस स्थान पर विराजमान प्रभु श्रीराम की मूर्ति के पास जाने के लिए अनेक ‘मेटल डिटेक्टर’ लगे हैं तथा वहां कोई भी वस्तु ले जाना प्रतिबंधित है । जांच पूर्ण कर सर्व प्रकार की पूजा और विधि के लिए आवश्यक सामग्री ले जाने की अनुमति दी जाए ।

आपका विश्वासपात्र,

(संपर्क :)